THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The matter is sub judice before the Madras High Court on a Petition moved by one Shri R. Sethuraman challenging the legality of foreign universities functioning in the country. While the case is yet to be finally disposed off, the honourable Court has permitted such universities to operate in the country subject to certain restrictions till the final disposal of the case.

छात्राओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ दिया जाना

1174. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली छात्राओं की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों हेतु वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों के पढ़ाई बीच में छोड़ देने की प्रवृत्ति की दर में निम्न रूप में गिरावट आई है:—

वर्ष	पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर
	I-V
1992-93	43.02%
1993-94	39.05%
1994-95 (अन्तरिम)	37.79%

(ग) पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर में कमी लाने के लिए सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं। इनमें सूक्ष्म आयोजना एवं सामुदायिक संघटन पंचायती राज संस्थाओं का अधिकाधिक सहयोग, आपरेशन ब्लैकबोर्ड द्वारा स्कूल के अवसंरचनात्मक ढांचे में सुधार, लड़कियों तथा अनु.जाति / अनु.जन जाति के छात्रों को प्रोत्साहन, शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, अध्ययन के न्यूनतम स्तरों का प्रतिपादन तथा मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना सम्मिलित है।

ओपन स्कूल घोटाला

1175. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओपन स्कूल में हुए घोटाले के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) की जांच रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और कौन-कौन से अधिकारियों को दोषी पाया गया है और उन्हें क्या सजा दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) से प्राप्त सूचना के अनुसार, जांच की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Expenditure on Fifth National Games

1176. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the total amount of expenditure financed by the Central Government to the Karnataka Government for the 4th National games held at Bangalore and Mysore;

(b) the amount of expenditure released by the Central Government to the Manipur Government for the development of 5th National games at Imphal; and

(c) the present progress report of sport infrastructures for the said games in Manipur?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI R. DHANUSHKODI ATHITHAN): (a) The Central Government had sanctioned Rs. 8.00 crore for creation of sports infrastructure and Rs. 1.50 crore for laying of synthetic surface/track in connection with the holding of 4th National Games in Karnataka.

(i) Main Stadium —Finishing stage.
(ii) Hockey Stadium —Nearing completion.
(iii) Velodrome —Casting of track started.
(iv) Indoor Stadium —Gallery Casting half completed. Roofing to be completed by January, 1998.
(v) Swimming Pool —Foundation work including piling over and casting to be completed by Nomvber, 1997.
(vi) Other minor items. —Nearing completion.

(b) Rs. 30.41 crore was released to the manipur Govcrnment for holding of 5th National Games at Imphal by the Central Government.

(c) The present progress report of sport infrastructures for the said games in manipur is as under:

आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना

1177. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना" के अधीन 1717 उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रस्ताव की लगात केवल सात करोड़ रु० ही थी, और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार राज्य को यह राशि कब तक उपलब्ध करायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तारित आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत 1770 उच्च प्राथमिक स्कूलों में लगभग 7.00 करोड़ रु० की लागत के शिक्षण अध्ययन उपस्कर प्रदान करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) निधियों का जारी करना राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श एवं अनुमोदन पर निर्भर करता है। राज्य सरकार से राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक का आयोजन करने का अनुरोध किया गया है।

Import of Gas

1178. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to import gas from Bangladesh; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) and (b) GAIL has signed a "Principles of Agreement" with Brown & Root International Inc., USA during March, 1996. The objective of the agreement is to examine techno-economics of having a gas pipeline from Myanmar and other countries in the region to carry gas to India. As per the agreement M/s Brown & Root International Inc., USA would be responsible to secure the gas volumes from the resource owners in Myanmar and other countries in the region and